परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- स्कूल शिक्षा विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, लोक शिक्षण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना	प्राथमिक से लेकर कालेज स्तर तक विद्यार्थियों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाना	50000	दुर्घटना होने पर लगभग 730 विद्यार्थियो के बीमा र प्रतिपूर्ति	
2	अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजो वर्ग के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना ।	3000000	कक्षा 1लीं से 8वीं तक 410000 एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक 35000 कुल 445000 विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है ।	
3	नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक का प्रदाय	कक्षा 01 से 10 तक के समस्त विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करना	500000	4716410 विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है ।	
4	नि:शुल्क गणवेश प्रदाय योजना	कक्षा 01 से 08 तक के अनु.जाति/जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क गणवेश प्रदान करना	550000	ए.पी.एल. छात्रों को नि:शुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है। 1342193 विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है।	
5	समग्र शिक्षा	06 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना	15040000	कक्षा 1लीं से 12वीं तक के 5271782 विद्याथियों व लाभावन्वित करने का लक्ष्य है।	
6	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण	1. प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के तह छात्रों की दर्ज संख्या में वृद्धि 2. छात्रों की उपस्थिति में नियमितता लाना (विशेषकर कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों) 3. शाला त्यागी बच्चों के दर में कमी लाना	7000000	समस्त शास. प्राथमिक शाला, शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शाला, पंजीकृत अनुदान प्राप्त मदरसों एवं बाल श्रम विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पक हुआ भोजन प्रदान किया जाता है । 2740527 विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है।	
7	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डी.ए. जुगा)	राज्य में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए परियोजना अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में छात्रावास निर्माण व शालाओं में संसाध सुविधाओं को बढ़ना एवं शालाओं के मरम्मत कार्यो आदि किया जाना ।	300006	अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में छात्रावास निर्माण व संसाधन सुविधाओं को बढ़ाना।	

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- स्कूल शिक्षा विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, लोक शिक्षण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
8	पुस्तकालय योजना	समस्त हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्य. शालाओं में ग्रंथालय की स्थापना कर विद्यार्थियों को पुस्तक उपलब्ध कराना	10000	राज्य के हाई स्कूल एवं उच्च.माध्य.विद्यालयों में इस योजना के तहत ग्रंथालय हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है । 100 शालाओं का लक्ष्य निर्धारित है ।	
9	छात्राओं को नि:शुल्क सरस्वती सायकल प्रदाय योजना	कक्षा 9वीं में प्रवेशित अनु.जाति एवं अनु. जनजाति की समस्त छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बढ़ावा	660000	शासकीय तथा शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं के कक्षा 09वीं में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति-जन जाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्राओं को नि:शुल्क सायकल प्रद किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है । 170968 छात्राओं का लक्ष्य निर्धारित है ।	
10	सैनिक स्कूल की स्थापना	ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करके सेना के अधिकारी वर्ग में प्रवेश के लिये तैयार करना ।	75000	अंबिकापुर जिले के मेण्ड्राकला में सैनिक स्कूल प्रारं किया गया है । 600 विद्यार्थी लाभान्वित होगें ।	
11	पी.एम.श्री योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत विभाग अंतर्गत संचालित शालाओं के भवन निर्माण, भवन मरम्म स्मार्ट क्लास इक्वीपमेंट, फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण आदि की व्यवस्था किया जाना ।	2500000	छत्तीसगढ़ में कुल 146 विकासखण्ड के लगभग 31 शालाएं	
12	टायपिंग बोर्ड का गठन	हिन्दी व अंग्रेजी शीघ्रलेखन-मुद्रलेखन परीक्षा तथ हिन्दी व अंग्रेजी की कौशल परीक्षा का (5000, 8000 एवं 10000 की डिप्रेशन) आयोजन करना	7500	लगभग 80000 विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का लक्ष्य है।	
13	मदरसा बोर्ड	धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा सुनिश्चित करना	30000	राज्य के पंजीकृत मदरसों के लगभग 12320 विद्यार्थियों को नि:शुल्क गुणवत्ता पूरक आधुनिक शि उपलब्ध कराया जाना है।	
14	संस्कृत बोर्ड	संस्कृत भाषा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा को	40000		

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- स्कूल शिक्षा विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, लोक शिक्षण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		मुख्यधारा से जोड़ना		15000 विद्यार्थियों को नि:शुल्क गणवेश, पाठ्य पुस्त एवं संस्कृत प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का लक्ष्य है ।	
15	शिक्षकों को पुरस्कार	शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्यों के लि पुरस्कृत किया जाता है ।	7731	1. राज्य शिक्षक पुरस्कार- प्रत्येक जिले के 02 शिक्षकों को कुल 66 शिक्षकों को पुरस्कार वितरण 2. मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण पुरस्कार संभाग स्तर पर प्रति संभाग 03 कुल 15 पुरस्कार, जिला स्तर पर प्रति जिला 03 कुल 99 एवं विकासखण्ड स्तर पर 03 शिक्षक कुल 438 पुरस्कार दिया जाता है । 3. विकासखण्ड स्तर पर प्राथमिक वर्ग के 01 व पूर्व माध्यमिक वर्ग के 01 कुल 292 उवं जिला स्तर पर हाई/हायर सेकण्डरी वर्ग के 01 कुल 33 शिक्षक क उत्कृष्ठ शिक्षक पुरस्कार दिया जाना है।	
16	कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना	कक्षा 06 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कन्याओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना	50000	अनुसूचित जाति वर्ग की 40000 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की 80000 कन्याओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का लक्ष्य है ।	
17	राज्य छात्रवृत्ति	कक्षा 03री से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को 10 माह के लिये राज्य छात्रवृत्ति देना	1500000	कक्षा 03री से 12वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 450000 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 800000 ए अन्य पिछड़ा वर्ग के 1175000 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का लक्ष्य है।	
18	नवभारत साक्षरता कार्यक्रम	केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-27 तक निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध असाक्षरों को साक्षर किया जाना है ।	71500	प्रदेश के 500000 असाक्षर को साक्षर करने का लक्ष है ।	

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- स्कूल शिक्षा विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, लोक शिक्षण

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
19	एकीकृत अम्ब्रेला योजना	अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्था की एकीकृत योजना	500000	कक्षा 09वी एवं 10वीं के 250000 छात्र- छात्राओं व छात्रवृत्ति दिये जाने का लक्ष्य है ।	
20	पी.एम. जनमन	राज्य में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए परियोजना अंतर्गत शालाओं में संसाधन सुविधाओं को बढ़ाना, शालओं के मरम्मत कार्यो आदि किया जाना।	300000	विभाग अंतर्गत संचालित शालाओं के भवन निर्माण, भवन मरम्मत, स्मार्ट क्लास इक्वीपमेंट, फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण, प्रशिक्षण, रिसर्च वर्क्स व सर्वे, पुस्तकों की छपाई तथा व्यावसायिक सेवाएं मानदेय हेतु।	
21	मॉडल स्कूल	राज्य में उच्च शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना	220000	शैक्षणिक रूप से पिछड़े 72 विकासखण्डों में पी.पी. मोड पर शाला संचालन कर 35500 विद्यार्थियो को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।	
22	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	प्रदेश में 10वी एवं 12वी कक्षा में प्रावीण्यता व आधार पर एकमुश्त एक बार प्रोत्साहन देना	10000	कक्षा 10वीं एवं 12वीं के अनुसूचित जाति के 300 एवं जनजाति के 700 कुल 1000 छात्र-छात्राओं को प्रावीण्य के आधार पर प्रति वर्ष एकमुश्त एक बार 15000/- प्रोत्साहन राशि वितरित की जाती है ।	